

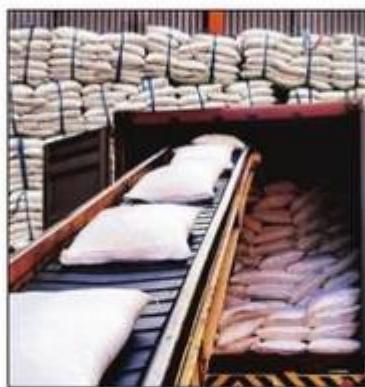
चीनी नियंत्रित करने वाली मिलों के लिए बढ़ेगा बिक्री का कोटा

तोहफा...बाजार में प्रतिमाह 21 लाख टन से ज्यादा चीनी बेच सकेंगे

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। चीनी नियंत्रित करने वाली और एथनॉल बनाने वाली मिलों को सरकार प्रोत्साहन देगी। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि मिलों को अतिरिक्त चीनी से एथनॉल बनाने की अनुमति होगी। इससे कमाई बढ़ेगी और किसानों का बकाया भुगतान करने में आसानी होगी।

मंत्रालय के अनुसार, अभी चीनी मिलों के लिए घरेलू बाजार में बिक्री का 21 लाख टन का मासिक कोटा तय है। जो मिलें नियंत्रित करती हैं या एथनॉल बनाने में अपनी चीनी का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अतिरिक्त कोटा दिया जाएगा। इससे मिलों को घरेलू बाजार में ज्यादा चीनी बेचने का मौका मिलेगा। हालांकि, इस बात से यह संकेत मिलता है कि अगले चीनी सत्र (अक्टूबर-सितंबर) से सरकार नियंत्रित सब्सिडी खत्म कर सकती है। अगले महीने समाप्त होने वाले मौजूदा चीनी सत्र में मिलों को 60 लाख टन चीनी नियंत्रित का कोटा मिला था, जबकि उन्हें 70 लाख टन



90,872 करोड़ रुपये का
गन्ना खरीदा
2020-21 में मिलों ने किसानों से

एथनॉल बनाने वाली चीनी मिलों को न सिर्फ अतिरिक्त चीनी खपाने का मौका मिलता है, बल्कि मोटी कमाई भी होती है। सरप्लस चीनी का इस्तेमाल होने से

एथनॉल बिक्री से मोटी कमाई बाजार में कीमतें भी प्रतिस्पर्धी बनी रहती हैं।

पिछले दो चीनी सत्र में मिलों को एथनॉल से 22 हजार करोड़ की कमाई हुई। 2020-21 में भी 20 लाख टन चीनी एथनॉल बनाने के लिए दी गई और 15 हजार करोड़ की कमाई हुई। अगले सत्र में 35 लाख टन चीनी एथनॉल बनाने में खपत होगी।

गन्ना किसानों को समय पर भुगतान संभव... चीनी मिलों की एथनॉल से कमाई बढ़ने पर किसानों का बकाया भुगतान करना आसान हो जाएगा। मिलों को 2019-20 सत्र के लिए किसानों को 75,845 करोड़ का भुगतान करना था, जिसमें से 75,703 करोड़ दिए जा चुके हैं। 2020-21 में रिकॉर्ड 90,872 करोड़ रुपये का गन्ना चीनी मिलों ने किसानों से खरीदा, जिसमें से अब तक 81,963 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 16 अगस्त, 2021 तक किसानों का 8,909 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। वैशिष्ट्यक बाजार में चीनी के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिससे नियंत्रितों के पास अगले सत्र में भी 60-70 लाख टन चीनी नियंत्रित का अवसर है।

का अनुबंध प्राप्त हुआ है। इसमें से 55 लाख टन चीनी अब तक नियंत्रित की जा चुकी है। 2017-18 में 62

लाख टन, 2018-19 में 38 लाख टन और 2019-20 में 59.60 लाख टन चीनी नियंत्रित हुआ था।